

प्राति आधारित जनगणना के विषय में तर्क/हानि

1. विभिन्न प्रातियों के महत्व विषय की प्राप्ति में वृद्धि तथा सामुदायिक सौहार्द्रता कमजोर।
2. सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्राति बढ़ाकर दर्ज करवाने की संभावना।
3. गलत सूचना से समानता एवं सामाजिक न्याय का लक्ष्य बाधित।
4. आरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न प्रातियों में संघर्ष एवं तनाव में वृद्धि की संभावना।
5. प्राति आधारित राजनीति को बढ़ावा और लोकतंत्र को स्वतंत्र।
6. आधुनिक समाज के निर्माण की प्रक्रिया बाधित।

समीक्षा -

निश्चित रूप से प्राति आधारित जनगणना के कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं - - - - -
परंतु भारत जैसे प्रातिपक्षान देश में जहां प्राति व्यवस्था कुछ परम्परागत रूप तथा कुछ नवीन स्वरूपों के साथ अपनी निरंतरता को बनाये हुये है और आरक्षण हेतु सामाजिक-
- शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार के रूप में क्रियाशील है - आधुनिक समाज के निर्माण के तर्क पर

प्राति आहारित जनगणना के लाभों को जाहिर नहीं किया जा सकता है।

इसलिए निष्कर्ष है कि -

समकालीन भारत में प्राति आहारित जनगणना की कुछ हानियों के बावजूद आवश्यक एवं प्रासंगिक है, क्योंकि इससे न केवल विकास योजनाओं को बांझित लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी बल्कि आरक्षण व्यवस्था का तार्किकीकरण भी संभव होगा और सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सकेगी।

संभावित प्रश्न -

1. भारत में प्राति आहारित जनगणना के औचित्य का परीक्षण कीजिए।
2. भारत में प्राति आहारित जनगणना, प्राति आहारित आरक्षण के तार्किकीकरण में कहां तक सहायक हो सकती है? उपयुक्त तर्कों के साथ उत्तर दीजिए।

उत्तर संरचना

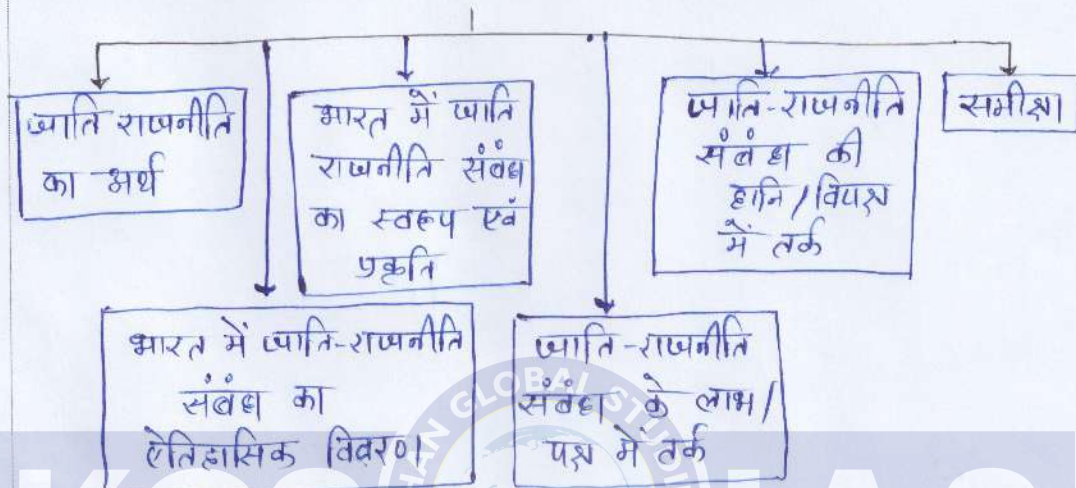
Part-1 :- आरक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य

Part-2 :- आरक्षण के संदर्भ में प्राति आहारित जनगणना की हानि

Part-3 :- आरक्षण के संदर्भ में प्राति आहारित जनगणना का लाभ

Part-4 :- समीक्षा (लाभ पर केन्द्रित)

भारत में जाति-राजनीति



KGS IAS

KHAN SIR